प्रतिदिन
लफ्ज की नब्ज

गुजरात के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए अपने एक इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन को भारतीय जनता पार्टी को बदलना पड़ा. पार्टी के विज्ञापन में पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया गया था. कहने की जरूरत नहीं कि भाजपा इस लफ्ज का इस्तेमाल राहुल गांधी का मखौल उड़ाने के इरादे से करती आई है. इसलिए अपने चुनावी विज्ञापन में भाजपा ने यही शब्द प्रयोग किया, तो सहज ही समझा जा सकता है कि उसकी मंशा क्या रही होगी. यों भी खासकर चुनाव के दौरान राजनीतिक विरोधी एक-दूसरे का मजाक बनाने से बाज नहीं आते. लेकिन निर्वाचन आयोग को उचित ही भाजपा का यह विज्ञापन आपत्तिजनक लगा, और आदर्श आचार संहिता के तकाजे के अनुरूप उसने इस विज्ञापन पर रोक लगा दी. आयोग की कार्रवाई से दो बातें जाहिर हैं. एक तो यह कि उसने भी माना कि पप्पू शब्द किसी काल्पनिक पात्र के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ही आया है. दूसरे, उसने यह भी स्वीकार किया कि इस तरह राहुल गांधी पर तंज कसा गया है.

इस विज्ञापन पर रोक लगाने की आयोग की कार्रवाई का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने एक दूसरा विज्ञापन जारी किया. बदले हुए विज्ञापन में युवराज शब्द का इस्तेमाल किया गया है. सबको मालूम है और आयोग को भी मालूम होगा कि युवराज शब्द के जरिए भाजपा राहुल गांधी पर निशाना साधती रही है. खुद मोदी अपने चुनावी भाषणों में राहुल गांधी की तरफ इशारा करने के लिए इस शब्द का प्रयोग बहुत बार कर चुके हैं. अलबत्ता बाद में राहुल गांधी के लिए युवराज के बजाय शहजादा शब्द का इस्तेमाल एक खास वजह से भाजपा को ज्यादा मुफीद लगने लगा. यह खास वजह क्या रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और अब शहजादा शब्द का इस्तेमाल भाजपा ने क्यों नहीं किया, यह भी आसानी से समझा जा सकता है. लेकिन सवाल है कि भाजपा के संशोधित विज्ञापन को आयोग ने मंजूरी कैसे दे दी? पप्पू शब्द में आयोग को तंज नजर आया था, पर यह बात तो युवराज शब्द की बाबत भी कही जा सकती है. ऐसा कई बार हुआ है जब आयोग के किसी निर्णय से तर्क का तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया. हाल ही में जब हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात के चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई, तो निर्वाचन आयोग को तीखे विवाद का सामना करना पड़ा.

कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दरम्यान लखनऊ के आंबेडकर मेमोरियल पार्क (डॉ भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल) में लगी हाथी की मूर्तियों को ढंकने का आयोग का फरमान तो बहुतसे लोगों को बहुत विचित्र लगा था. चुनाव होने तक उन मूर्तियों को ढंक कर रखने के आदेश के पीछे वजह यही थी कि हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिह्न है. लेकिन आयोग के उस आदेश के चलते हाथी और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था. सवाल उठाया गया था कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हों, और सड़क पर या विवाह जैसे किसी समारोह की शोभा बढ़ाता जीवित हाथी दिखे, तो क्या उसे भी आचार संहिता के विपरीत मान कर कार्रवाई की जाएगी! बहरहाल, एक संवैधानिक संस्था के रूप में आयोग की काफी साख रही है. देश के भीतर ही नहीं, बाहर भी. इसलिए उम्मीद की जाती है कि उसके निर्णय हर तरह से सुसंगत होंगे.

सेना को मिले ज्यादा स्वतंत्रता

भारतीय सेना पूरी दुनिया में अपने पेशेवर अंदाज, दृढ़ता और बेहतर आचरण के लिए जानी जाती है. इसे उस उपमहाद्वीप की एकमात्र गैरराजनीतिक सेना होने का गौरव प्राप्त है, जहां सेना सरकार पर हावी होने के लिए कुख्यात हैं. एक लोकतांत्रिक परिवेश में इसने अपना जज्बा अब भी बरकरार रखा है, हालांकि सरकार की तरफ से इसे कमतर बताने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी गई है. यह अफसोस की बात है कि जिस भारतीय सेना का सम्मान पूरी दुनिया करती है, खुद वहां के अपने नौकरशाह और राजनीतिक विश्लेषक इसे निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

ऐतिहासिक तौर पर देखें, तो भारतीय सेना ने ब्रिटिश काल में दोनों विश्वयुद्धों में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र के कई अभियानों में हिस्सा लिया है. जहां कहीं भी इसे काम करने का मौका मिला, इसने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया. हाल ही में इस्राइल ने हाइफा के युद्ध के लिए भारतीय सैनिक के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है. गौरतलब है कि 1918 में हाइफा के युद्ध में भारत के अनेक योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया. गौरतलब है कि इस्राइल के समुद्र तटीय शहर हाइफा की मुक्ति से ही आधुनिक इस्राइल के निर्माण की नींव पड़ी थी. इसी तरह बांग्लादेश की मुक्ति में भारतीय सेना का प्रदर्शन सैन्य इतिहास के अध्ययन का विषय बना हुआ है. भारतीय सेना की छवि एक ऐसे सैन्य बल की है, जिसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाया है.

हालिया वर्षों में भारतीय सेना विभिन्न राष्ट्रों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है. भारत, जापान और अमेरिका के साथ होने वाले मालाबार नौसेनाभ्यास का मकसद चीन को कड़ा संदेश देना है. अब इसमें ऑस्ट्रेलिया के भी शामिल होने की उम्मीद है. इस संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चीन ने हमेशा टेढ़ी नजर रखी है, क्योंकि वह भारत की नौसैन्य शक्ति को अपने लिए एक खतरे की तरह देखता है.

यही नहीं, भारत दूसरे देशों की सेना के लिए प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है. इन प्रशिक्षणों को ग्रहण करने वाले दूसरे देशों के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ जीवन भर रहने वाला एक जुड़ाव साथ लेकर लौटते हैं. यह जुड़ाव, शिष्टता और भारतीय संस्कृति को निकट से समझने का मौका दूसरे देशों के इन सैनिकों के मन में भारतीय सेना और भारत के प्रति एक आदर भाव पैदा करता है. हालांकि शायद ही कभी कोई ऐसा होता हो, जब प्रशिक्षण के दौरान भारतीय सेना दूसरे मुल्कों के सैनिकों को अपने पेशेवर अंदाज की चमक न दिखाती हो.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेना को एक नई पहचान दिलाने के इन प्रयासों का उद्देश्य है कि इसकी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जाए. भारतीय सेना की सॉफ्ट पावर को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान की सेना भारतीय सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण ले रही है. इस प्रशिक्षण से अफगान सेना को जो अनुभव, ज्ञान, हथियारों की समझ और भारतीय सेना को निकट से समझने का मौका मिलेगा, जिससे वह इतनी काबिल हो सकेगी कि पाकिस्तान की ओर से मिलने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सके. जब पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख ने अपनी अफगानिस्तान यात्रा के दौरान वहां की सेना को प्रशिक्षण देने की इच्छा जाहिर की, तब अफगानिस्तान की ओर से उन्हें कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली. चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत और चीन की सेना एकदूसरे की धरती पर संयुक्त सैन्याभ्यास करती रहती हैं. इससे दोनों ही मुल्कों को एक-दूसरे की क्षमता और पेशेवर रवैये को समझने का मौका मिलता है. जब तक सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकलता, दोनों देशों के बीच आने वाले वर्षों में तनातनी तो बनी रहेगी, लेकिन बात फिर भी युद्ध तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि एकदूसरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

भारतीय सेना की सॉफ्ट पावर अपने चढ़ाव पर है. हालांकि सर्व विवादित है कि आयातित हथियारों के दम पर कोई भी देश कभी महाशक्ति नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने हर बार हर मोर्चे पर अपना दम दिखाया है. सैन्य सॉफ्ट पावर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, हालांकि भारत सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाने से हिचकती आई है. दरअसल, आंतरिक या फिर बाहरी संकटों से जूझ रहे देशों में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को सहारा देने के लिए सेना की भूमिका बढ़ जाती है. ऐसे देशों की सेना के साथ संपर्क बढ़ाकर हमारा सैन्य नेतृत्व कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बना सकता है. बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और फिलीपींस के अलावा सुदूर में बोको हराम से लड़ रहे अफ्रीकी देश ऐसे ही कुछ देशों के उदाहरण हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेना को एक नई पहचान दिलाने के इन प्रयासों का उद्देश्य है कि इसकी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जाए. भारतीय सेना की सॉफ्ट पावर को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान की सेना भारतीय सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण ले रही है. इस प्रशिक्षण से अफगान सेना को जो अनुभव, ज्ञान, हथियारों की समझ और भारतीय सेना को निकट से समझने का मौका मिलेगा, जिससे वह इतनी काबिल हो सकेगी कि पाकिस्तान की ओर से मिलने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सके.

सेना की सॉफ्ट पावर का ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए संयुक्त सैन्याभ्यासों का सही समय पर होते रहना और दूसरे देशों को समय पर कोर्स उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है. मगर इसके लिए सेना और विदेश मंत्रालय के बीच सटीक तालमेल अनिवार्य है.

लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सैन्य बल रक्षा मंत्रालय का हिस्सा न होकर उसके अधीन जैसी भूमिका में होते हैं. ऐसे में सूचनाओं के प्रवाह में विलंब होता है, जिससे सारा तालमेल धरा का धरा रह जाता है.

पूरी दुनिया में बढ़ते खतरों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग ज्यादा जरूरी हो गया है. हालांकि किसी अंतरराष्ट्रीय संकट के मामले में अपनी सेना के बेवजह हस्तक्षेप जैसी भारत की कोई मंशा नहीं है, बशर्ते कोई अभियान संयुक्त राष्ट्र के ध्वज तले न हो रहा हो, या फिर भारतीय हितों की सुरक्षा का सवाल न हो. भारत को अपनी सैन्य सॉफ्ट पावर का उपयोग करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का दायरा भी बढ़ाना चाहिए. ऐसा हो सके इसके लिए जरूरी है कि सरकार के भीतर संवाद और वार्ता से जुड़ी जो वर्तमान अड़चने हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए और सैन्य बलों को ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए. **हर्ष कक्कड़**

प्रतिदिन
रेत का पुल

भारद्वाज ऋषि के पुत्र यवक्रीत को विद्यार्जन में रुचि नहीं थी. इसलिए वह अध्ययन से दूर रहे पर बाद में उन्हें अहसास हुआ कि अशिक्षित होने और शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण समाज में उनका सम्मान नहीं होता. लेकिन चूंकि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, विधिवत शिक्षा ग्रहण करने का समय निकल चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न देवताओं की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और वरदान मांग कर सारी विद्याएं प्राप्त कर ली जाएं. वह गंगा किनारे भगवान को खुश करने के लिए ध्यानमग्न हो गए. भगवान इंद्र उनके मन की बात समझ गए. एक दिन वह साधु का वेश धारण करके वहां आए और दोनों हाथों से रेत उठा कर पानी में डालने लगे. थोड़ी देर में यवक्रीत की आंखें खुलीं. उन्होंने साधु को पानी में बालू डालते देख कर पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं. साधू ने कहा, गंगा के ऊपर पुल बना रहा हूं. यवक्रीत ने कहा, आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं. लेकिन यह मूर्खता वाला काम क्यों कर रहे हैं. कहीं बालू से पुल बनता है बालू तो पानी में गिरते ही उसमें घुल जाता है. यह सुनकर साधु ने कहा, यदि बिना पढ़े-लिखे ज्ञान मिल सकता है तो बालू से पुल क्यों नहीं बन सकता. अगर तपस्या करने से ही ज्ञान मिलता तो फिर पढ़ने-लिखने का कष्ट कौन उठाता.सभी आप की तरह तपस्या करके भगवान को खुश करके ज्ञान का वर मांग लेते यह सुनकर यवक्रीत सोच में पड़ गए. उन्होंने कहा, पर इतनी ज्यादा उम्र में पढ़ाई कौन करता है. साधु ने कहा, वत्स, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती. यदि आप संकल्प कर लोगे तो अब भी अपने पिता के समान महान ज्ञानी बन सकते हो. यवक्रीत ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं.अब मैं अध्ययन करूंगा. बाद में यवक्रीत महान विद्वान बने और तपोदत्त के नाम से जाने गए.

नेटीजन
मुजीब और इंदिरा

बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष को समर्थन देने का फैसला लेकर उन्होंने बड़ा जोखिम मोल लिया था.

मुझे आज भी याद है, जब 1975 में इंदिरा गांधी की बंगबंधु के साथ जमैका में मुलाकात हुई थी. उन्होंने शेख मुजीब की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की. उन्हें खुफिया एजेंसियों से इसकी जानकारी मिली थी कि बंगबंधु की जान को खतरा है, लेकिन शेख मुजीब को यह भरोसा था कि कोई बंगाली उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर 15 अगस्त, 1975 को शेख मुजीबुर रहमान साजिश का शिकार हो गए. इसके कुछ महीनों बाद नई दिल्ली में मेरी इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा कि यह कितने दुख की बात है कि जिस साजिश को लेकर उन्होंने बंगबंधु को सावधान किया था, वह हकीकत में बदल गया. इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको भी अपनी सुरक्षा के वास्ते आवश्यक कदम उठाने चाहिए. इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्हें इस तरह का कोई डर नहीं है. इस मुलाकात के कुछ अरसे बाद वह भी हत्या की साजिश का शिकार हो गईं. इंदिरा गांधी से कई मुलाकातें हुईं और मैं उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर देखता हूं, जो राष्ट्रहित में मुश्किल फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकती थीं. मुडो मालूम है कि बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष को समर्थन देने का फैसला लेकर उन्होंने कितना बड़ा जोखिम मोल लिया था.

बीबीसी में कमाल हुसैन
(पूर्व विदेश मंत्री, बांग्लादेश)

दृष्टिकोण...
सेक्स सीडी से उपजे कई सवाल

पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की कथित सेक्स सीडी से गुजरात में सियासी पारा गर्म है. इस तरह की सीडी गुजरात की राजनीति को प्रभावित करेगी, ऐसा नहीं लगता और न ही इसका सरोकार सीधे तौर पर जनता से है. यह ओछी राजनीति का उदाहरण भर है.

गुजरात में चुनावी गहमागहमी के बीच सेक्स सीडी किसने वायरल की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना किसी पुख्ता सुबूत के यह साबित करने में लग गए कि ये सीडी बीजेपी ने वायरल की है. जाहिर तौर पर ऐसी सीडी चुनाव से ऐन पहले सार्वजनिक करना और किसी की निजता में दखल देना किसी रूप से जायज नहीं है. हार्दिक पटेल ने भी इसे राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए ीकरा बीजेपी के सिर मढ दिया. उनके आरोपों में सच्चाई कम राजनीतिक चतुराई स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है. अभी कुछ रोज पहले ही हार्दिक ने अंदेशा जताया था कि उनको बदनाम करने के लिए बीजेपी कोई वीडियो वायरल कर सकती है. हार्दिक का बयान और सेक्स सीडी का सामने आना कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि सीडी कांड पूर्व नियोजित था.हार्दिक के बयानों को समझें तो कई तथ्य सामने आते हैं, जो खुद इस सीडी कांड की कहानी को बयां करने के लिए काफी है. पहला सवाल क्या हार्दिक को पता था कि उनकी कोई सेक्स सीडी बनी है. अगर पता था तो उन्होंने उस वक्त खुलासा क्यों नहीं किया. किसी भी व्यक्ति को अंदेशा होता है कि उसकी निजता में कोई दखल दे रहा है तो सबसे पहले वह उस पर कार्रवाई करता है किन्तु वह मौन रहे. किसी के भी निजी जीवन में ताक झांक किसी रूप में सही नहीं है, पर इस पर चुप बै ना भी संशय पैदा करता है. यह राजनीतिक नफा नुकसान के मद्देनजर वायरल की गई सीडी है. सीडी कांड को गुजरात की नारी के सम्मान से जोडकर हार्दिक ने साबित किया है कि वह किसी भी स्तर की राजनीति से परहेज नहीं करने वाले. सीडी जारी करने में बीजेपी पर आरोपों की बात करें, तो इसके ोस कारण नजर नहीं आते. राज्य में पार्टी मजबूत स्थिति में है. हाल मे जो चुनावी सर्वे आए हैं, उसमें बीजेपी को बढत मिलती दिख रही है. इससे हार्दिक पटेल, कांग्रेस समेत उनके साथी हताशा के दौर से गुजर रहे हैं. हार्दिक भले ही खुद को बडा नेता मान बै ` हों पर सच्चाई यह है कि आज भी उनके पास सियासी जमीन नहीं है. यह पहले से सर्वविदित है कि तमाम दिखावे के बाद हार्दिक कांग्रेस से ही हाथ मिलाएंगे. सीडी कांड गुजरात की सियासत में कोई बडा उलटफेर लाएगी. ऐसा नहीं है, पर हार्दिक की राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही बडा झटका जरूर है.

आदर्श तिवारी
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार है

इंटरनेशनल मीडिया
बलूचिस्तान में खूनखराबा

बलूचिस्तान हादसों और हिंसा की गिरफ्त में लगातार बना हुआ है. मौत का सिलसिला जारी है. यह सही है कि बीच में इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ी थी, मगर एक बार फिर इसमें तेजी आ गई है. बीते बुधवार को घटी दो घटनाएं इसकी तस्दीक करती हैं. क्वेटा के नवां किल्ली इलाके की वारदात में मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दो ने एसपी मुहम्मद इलियास को उनके घर के करीब ही मार डाला. इस हमले में उनकी बीवी, बेटा और छह साल का पोता भी मारे गए, पोते से भी छोटी पोती बुरी तरह जख्मी हो गई. इलियास इस इलाके के दूसरे बड़े पुलिस अफसर हैं, जो एक महीने के भीतर मारे गए हैं. वहां पर तरहतरह की कट्टरपंथी जमातें सक्रिय हैं, हालांकि अब तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं कबूली है. हिंसा की एक अन्य कार्रवाई में ईरान से लगे सरहदी इलाके तुरबत में 15 लोग मारे गए. ये सभी लोग पंजाब के अलगअलग हिस्से के थे और कुछ रोज पहले ही इन सभी को अगवा किया गया था. ये सभी ईरान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वहां से आगे गैरकानूनी प्रवासी के रूप में यूरोप में प्रवेश कर सकें. मगर उनका सफर अपने मुल्क की सरहद में ही पूरा हो गया. उनकी बदनसीबी की खबर उनके शहर, गांव और टोलों में पहुंच चुकी है और इसने इन सबके खानदानों के अलावा दूसरे बाशिंदों की हताशा को और गहरा दिया है. ये दोनों ही हमले ठीक उसी दिन हुए, जब नेशनल सिक्युरिटी कमिटी बलूचिस्तान की सुरक्षाव्यवस्था की समीक्षा करने बैठी थी. इन घटनाओं ने उजागर किया है कि कितना कुछ करना अभी बाकी है. बहरहाल, कमिटी ने फैसला किया है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए और अधिक संसाधन लगाए जाएंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि सिर्फ पैसे से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता. आईएस जैसे आतंकी संगठन बलूचिस्तान में अपनी जड़ें जमाने में सक्षम हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकने की जरूरत है. बलूचिस्तान में शांति कायम करने का एकमात्र रास्ता स्मार्ट तरीके से कानून लागू करने के साथ वह समझदारी विकसित करना भी है, जो बलूच लोगों को संतुष्ट कर सके.

आपकी बात
बस स्टैंड पर आवाजाही बाधित, मूक बनी ट्रैफिक पुलिस

फिलहाल शहर में सर्वत्र मुख्य रास्ते खोदकर नए बनाने के कार्य हेतु अस्थाई रूप से बंद किए गए है और पर्यायी रास्तों पर आवाजाही बढ़ गई है. जिससे यातायात पुलिस विभाग पर दबाव व तनाव बढ़ गया है. ट्रेफिक पुलिस यातायात अबाधित रखने हेतु कार्य में जुटी हुई है. किंतु यातायात सुरक्षित व अबाधित रखने के लिए मनपा अतिक्रमण विभाग व ट्रेफिक विभाग ने संयुक्त रूप से कठोर कदम उठाना आवश्यक है. मध्यवर्ती बस स्टैंड का मुख्य मार्ग बंद होने के बावजूद भी सुबह 9 बजे तक यातायात पुलिस न होने के कारण अतिक्रमण, ऑटो चालकों की अवैध पार्किंग को प्रोत्साहित करते है. चाय टपरी, नाश्ते की गाड़ियां, ऑटो वाले बस निकलने वाले प्रवेशद्वारा पर खड़े कर देते है. यातायात पुलिस तैनात न हो के कारण पहला विभागीय शहर होगा जहां बस स्टैंड पर दिनभर यातायात बाधित दिखता है. ट्रेफिक पुलिस का यहां होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. बडनेरा जाने वाले ऑटो सीधे रास्ते पर यात्रियों की तलाश में इधर-उधर भटकते हुए दिखते है, साथ ही पानटपरी पर खुलेआम गुटका बेचते हुए यहीं दिखता है. इसके साथ ही निजी ट्रेव्हल्स भी हर 15 मिनीट में बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए चक्कर काटती है. बस स्टैंड के समक्ष सायन्सकोर मैदान तो रात के समय शराब का अड्डा बन रहता है. पुलिस आयुक्त साहब जो रास्ते फिलहाल आने-जाने के लिए शुरू है वहां अवैध पार्किंग, अतिक्रमण हटाने की कृपा कर शहरवासियों को राहत दे. **मंगेश मोरे, अमरावती**

प्रतिदिन अखबार
यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर 'प्रतिदिन अखबार' कार्यालय, देविका परिसर, ब्राह्मण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444 606 से प्रकाशित किया है. फोन-0721-2560155/56/57/58 फैक्स-0721-2677708 E-mail :- pratidinnews@gmail.com
'प्रतिदिन अखबार' में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र, साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का ही दायित्व है. संपादक-नानक आहूजा, समाचार संपादक-प्रवीण आहूजा.